In the Fifth Plan the development of tourist facilities at Konark has been included in the Cultural Tourism Programme of the Department of Tourism. Accordingly, a master plan (land-use plan) of the area surrounding the Sun Temple has been prepared. Allocation of facilities and environmental planning are also incorporated in the master-plan. Based on the master plan, detailed schemes will be drawn up for providing facilities such as accommodation, transport, water, electricity and other amenities.

Restructuring of the Administration of the Co-operative Department

2964. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to restructure the administration of the Cooperative Department and amend the existing cooperative law so as to make it more responsive to the needs of the people;

(b) whether Government have taken up the matter of reduction of payment of interest on the loan given by the Reserve Bank of India to different co-operative banks and societies of different States; and

(c) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES & COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Cooperation being a State subject, the responsibility for the supervision of cooperative societies vests in the State Governments. The Government of India also lay considerable stress on the need for the cooperatives to serve a larger number of persons, especially the weaker sections of the community. For this purpose, a set of guidelines has been circulated to the States for undertaking suitable modification to their cooperative laws. The States have been advised to incorporate suitable provisions in their laws providing for automatic membership to persons who are duly qualified for admission as members under the provisions of the Act, the Rules and the Bye-laws. Similarly, the State Governments have been advised to amend their laws to provide for compulsory reservation of seats in favour of the weaker sections, on the committee of management of primary agricultural societies. These provisions are intended to ensure that cooperatives cater to the needs of a larger section of the rural population.

(b) and (c). No, Sir.

गाजियाबाद में कारखाना मालिकों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

2965. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के कुछ कारखाना मालिकों को, जिन्होंने आपातकाल के दौरान कारखाने लगाये, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बम्बई द्वारा काफी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) गत दो वर्षों में गाजियाबाद के कितने तथा किन-किन मिल मालिकों को दो लाख से अधिक राशि के ऋण केन्द्रीय सरकार की वित्त एजेंसियों द्वारा दिये गये;

(ग) क्या इन में से कुछ मिलें कल्पित हैं और ये ऋण सिफारिशों के आधार पर दिये गये;

(घ) क्या सरकार इस बारे में पूरी जांच कराने के पश्चात् तथ्यों को सभा पटल पर रखेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और इन कल्पित मिलों को दिये गये ऋणों को किस प्रकार वसूल किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सुपर बाजार के अध्यक्ष

2966. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में सुपर बाजारों के अध्यक्ष कौन-कौन ह और वे किस दलों से सम्बन्धित हैं;

(ख) अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है और क्या वर्तमान अध्यक्ष ने अपने पद से हटने का प्रस्ताव किया है;

(ग) वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में सरकार को सुपर बाजारों से कितनी हानि अथवा लाभ हुआ;

(ग) सुपर बाजारों की कार्यकुशलता से वृद्धि करने तथा उनसे अधिक लाभ कमाने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं और क्या कोई परामर्शदात्री समिति भी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). कांग्रेस पार्टी की संसद् सदस्या (राज्य सभा), श्रीमती सविता बहन सरकार द्वारा 7 अप्रैल, 1972 को को-आपरेटिव स्टोर लि०, जो दिल्ली में सुपर बाजार तथा उसकी शाखाओं को चलाता है, की अध्यक्षा नामित की गई थीं। उन्होंने को-आपरेटिव स्टोर के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया है, जो 17-5-1977 से स्वीकार किया गया। को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड की उप-विधियों के अनुसार को-आपरेटिव स्टोर के अध्यक्ष के नामांकन तथा प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस अवधि में सुपर बाजार ने नीचे दिया गया लाभ कमाया :—

	लाख रु०	
1972-73	0.51	(लेखा परीक्षित)
1973-74	10.66	वही
1974-75	4.46	(अनन्तिम, लेखा परीक्षा अभी होनी है)
1975-76	7.76	वही

(घ) सुपर बाजार के लिए कोई सलाहकार समिति नहीं है। इस संस्था का प्रबन्ध सरकार द्वारा नामित प्रबन्ध समिति द्वारा चलाया जाता है, जैसा कि को-आपरेटिव स्टोर की उपविधियों में दिया गया है। तथापि, वस्तु सूची नियंत्रण में सुधार करने और चोरी आदि से होने वाली हानियों को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गये ह।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कथित कदाचार

2967. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को इस आधार पर सेवा निवृत्त कर दिया गया था कि आपातकालीन स्थिति के दौरान किये गये उनके कार्य उनके पद के अनुरूप नहीं थे ;